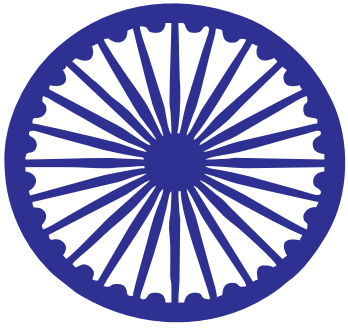




नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01

अंक : 277

दि. 10.07.2026,

शुक्रवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

कर्नाटक में जाति जनगणना रिपोर्ट पर सियासी संग्राम तेज, कैबिनेट के फैसले पर टिकी निगाहें; भाजपा ने सदन में रिपोर्ट रखने की मांग, कांग्रेस ने दी ‘पहले अपने राज्यों में कराएं सर्वे’ की चुनौती

बेंगलुरु। कर्नाटक में लंबे समय से चर्चा का विषय बनी जातिगत जनगणना (सामाजिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण) की रिपोर्ट एक बार फिर राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गई है। रिपोर्ट पर सरकार के अंतिम फैसले से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा ने राज्य सरकार से रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने, उसे सार्वजनिक करने और उस पर स्पष्ट रख अपनाने की मांग की है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए चुनौती दी है कि यदि वह वास्तव में जाति जनगणना की समर्थक है तो पहले उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इसी प्रकार का सर्वेक्षण कराए। इस बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट पर कोई भी अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल में विस्तृत चर्चा के बाद ही लिया जाएगा।

राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट अभी

तक कैबिनेट के समक्ष औपचारिक रूप से प्रस्तुत नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जब रिपोर्ट मंत्रिमंडल के सामने आएगी, तब उसके सभी कानूनी, सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके बाद ही सरकार यह तय करेगी कि रिपोर्ट की सिफारिशों को किस रूप में लागू किया जाए या आगे की प्रक्रिया क्या होगी। प्रियांक खरगे ने भाजपा की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा का रुख विरोधाभासी है। यदि पार्टी वास्तव में जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय का आधार मानती है तो उसे सबसे पहले अपने शासन वाले राज्यों में इस प्रकार का सर्वेक्षण कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार 'जितनी आबादी, उतना हक' के सिद्धांत की बात करती रही है और यदि भाजपा भी इस विचार से सहमत है तो उसे पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए।

उधर भाजपा ने सरकार के रुख पर सवाल



उठाते हुए कहा है कि जिस सर्वेक्षण पर जनता के करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने

से सरकार क्यों बच रही है। भाजपा के प्रदेश महासचिव और विधायक वी. सुनील कुमार ने कहा कि सामाजिक एवं

शैक्षणिक सर्वेक्षण पर 450 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि रिपोर्ट

विधानसभा के पटल पर रखी जाए ताकि सभी राजनीतिक दल और जनता उसके निष्कर्षों पर खुलकर चर्चा कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह रिपोर्ट स्वीकार करती है या नहीं तथा उसकी सिफारिशों पर क्या कार्रवाई करने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जातिगत जनगणना की यह रिपोर्ट केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, बल्कि आगामी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। रिपोर्ट में विभिन्न जातीय और सामाजिक वर्गों की जनसंख्या, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं तक पहुंच से जुड़े आंकड़े शामिल बताए जा रहे हैं। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल इसके संभावित प्रभाव को देखते हुए अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं।

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसी वर्ष मई महीने में पिछड़ा वर्ग आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष मधुसूदन

नायक से यह रिपोर्ट प्राप्त की थी। इसके बाद से लगातार यह चर्चा चल रही है कि सरकार इसे कब सार्वजनिक करेगी और इसकी सिफारिशों पर क्या निर्णय लेगी। हालांकि अब तक सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है, जिससे विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस बीच किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा भी राज्य की राजनीति में गरमा गया है। प्रियांक खरगे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि भाजपा किसानों के लिए 50 हजार रुपये तक की कर्जमाफी की मांग कर रही है तो उसे केंद्र सरकार से भी इसी प्रकार की पहल करने के लिए कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही कई केंद्रीय योजनाओं में अपना वित्तीय योगदान दे रही है और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए केंद्र सरकार को भी बराबर की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वहीं उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि सरकार फिलहाल राज्य के सूखा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत

आकलन करा रही है। संबंधित विभागों से रिपोर्ट मिलने के बाद ही किसानों की कर्जमाफी सहित अन्य राहत उपायों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी फैसले से पहले वित्तीय स्थिति और वास्तविक नुकसान का पूरा मूल्यांकन करेगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कर्नाटक में जातिगत जनगणना का मुद्दा आने वाले दिनों में और अधिक गर्मा सकता है। कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व से जोड़कर पेश कर रही है, जबकि भाजपा पारदर्शिता और रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग के जरिए सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। ऐसे में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे पर तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। अब सभी की नजर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि बहुचर्चित जातिगत जनगणना रिपोर्ट का भविष्य क्या होगा और सरकार उसकी सिफारिशों पर किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

डब्ल्यूएचओ की चेतावनी: 2050 तक दुनिया में हर साल 3.5 करोड़ नए कैंसर मरीज, हर पांच में से एक व्यक्ति के प्रभावित होने का अनुमान

जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कैंसर को लेकर गंभीर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि वर्तमान रुझान जारी रहे तो वर्ष 2050 तक दुनिया में हर साल कैंसर के नए मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 3.5 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान में यह आंकड़ा करीब 2.06 करोड़ नए मामलों का है। डब्ल्यूएचओ की ताजा 'ग्लोबल स्टैट्स रिपोर्ट ऑन कैंसर 2026' के अनुसार, वैज्ञानिक प्रगति, नई दवाओं और आधुनिक उपचार तकनीकों के बावजूद दुनिया के करोड़ों कैंसर मरीज आज भी समय पर जांच, उपचार और आर्थिक सहायता जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कैंसर केवल स्वास्थ्य चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्तर पर भी वैश्विक संकट का रूप लेता जा रहा है। डब्ल्यूएचओ और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार इस रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले वर्षों में हर पांच में से एक व्यक्ति को जीवनकाल में किसी न किसी प्रकार का कैंसर होने की आशंका है। रिपोर्ट का अनुमान है कि दुनिया के 92 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कैंसर से प्रभावित होंगे। यानी या तो वे स्वयं इस बीमारी का सामना करेंगे या उनके परिवार का कोई करीबी सदस्य कैंसर से पीड़ित होगा। डब्ल्यूएचओ में कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के प्रमुख डॉ. आंद्रे इल्वाबी ने कहा कि पिछले वर्षों में कैंसर उपचार

को लेकर वैज्ञानिक उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। नई तकनीकों, बेहतर दवाओं और आधुनिक उपचार पद्धतियों ने मरीजों के लिए उम्मीद बढ़ाई है, लेकिन यह तस्वीर का केवल एक पक्ष है। उन्होंने कहा कि वास्तविक चुनौती यह है कि दुनिया के करोड़ों लोगों तक यह आधुनिक इलाज अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है। आर्थिक असमानता, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और समय पर जांच न होने के कारण बड़ी संख्या में मरीजों की जान बचाई नहीं जा पा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में दुनिया भर में हर दिन 26 हजार से अधिक लोग की मौत कैंसर से होती है, जबकि हर वर्ष लगभग एक करोड़ लोगों की जान इस बीमारी के कारण चली जाती है। यही वजह है कि कैंसर अब हृदय रोगों के बाद दुनिया में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि रोकथाम, शुरुआती जांच और उपचार तक समान पहुंच प्रशिक्षित नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में हर पांच में से एक व्यक्ति को जीवनकाल में किसी न किसी प्रकार का कैंसर होने की आशंका है। रिपोर्ट का अनुमान है कि दुनिया के 92 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कैंसर से प्रभावित होंगे। यानी या तो वे स्वयं इस बीमारी का सामना करेंगे या उनके परिवार का कोई करीबी सदस्य कैंसर से पीड़ित होगा। डब्ल्यूएचओ में कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के प्रमुख डॉ. आंद्रे इल्वाबी ने कहा कि पिछले वर्षों में कैंसर उपचार

सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं हो पातीं, जिससे मृत्यु दर बढ़ जाती है। रिपोर्ट में आय के आधार पर देशों के बीच उपचार की उपलब्धता में भारी अंतर भी सामने आया है। उच्च आय वाले देशों में स्तन कैंसर से पीड़ित लगभग 87 प्रतिशत महिलाएं निदान के बाद कम से कम पांच वर्ष तक जीवित रहती हैं, जबकि कम आय वाले देशों में यह आंकड़ा घटकर लगभग 42 प्रतिशत रह जाता है। इसका मुख्य कारण समय पर निदान, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता और आधुनिक उपचार सुविधाओं तक सीमित पहुंच है। डब्ल्यूएचओ ने यह भी बताया कि दुनिया के तीन में से एक से भी कम देशों ने अपने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कार्यक्रम में व्यापक कैंसर उपचार को शामिल किया है। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मरीजों को अपनी जेब से भारी खर्च करना पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 45 प्रतिशत कैंसर मरीज और उनके परिवार इलाज के दौरान गंभीर आर्थिक संकट का सामना करते हैं, जबकि आधे से अधिक मरीज मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, जैसे अवसाद, तनाव और चिंता से भी प्रभावित होते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो 2024 में एशिया में दुनिया के आधे से अधिक कैंसर के मामले और मौतें दर्ज की गईं, जबकि यूरोप में 21 प्रतिशत नए मामले और लगभग 20 प्रतिशत मौतें हुईं। विशेषज्ञों का मानना है कि एशिया की विशाल आबादी, तेजी से

बदलती जीवनशैली, तंबाकू सेवन, प्रदूषण और उम्रदराज होती जनसंख्या इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं। रिपोर्ट में भारत को भी कैंसर से सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल किया गया है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, भारत जैसे निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में कैंसर उपचार के लिए आवश्यक 20 प्रमुख दवाओं की उपलब्धता केवल 9 से 54 प्रतिशत के बीच है, जबकि विकसित देशों में यही उपलब्धता 68 से 94 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएसआर) और राष्ट्रीय आधुनिक उपचार सुविधाओं तक सीमित पहुंच को भारत में हर वर्ष करीब 14.6 लाख से 15 लाख नए कैंसर मरीज सामने लाते हैं। वर्तमान समय में देश में लगभग 25 लाख लोग कैंसर के साथ जीवन जी रहे हैं। अनुमान है कि यदि रोकथाम और उपचार की व्यवस्था में व्यापक सुधार नहीं हुआ तो 2050 तक भारत में हर वर्ष कैंसर के नए मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 28 लाख तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर से बढ़ते खर्चों को कम करने के लिए केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, जैसे अवसाद, तनाव और चिंता से भी प्रभावित होते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो 2024 में एशिया में दुनिया के आधे से अधिक कैंसर के मामले और मौतें दर्ज की गईं, जबकि यूरोप में 21 प्रतिशत नए मामले और लगभग 20 प्रतिशत मौतें हुईं। विशेषज्ञों का मानना है कि एशिया की विशाल आबादी, तेजी से

नई दिल्ली। भारत में डायबिटीज के इलाज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डेनमार्क की वैश्विक दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने देश में पहली बार सप्ताह में एक बार दिए जाने वाले बेसल इंसुलिन निम्न-मध्यम आय वाले देशों में कैंसर उपचार के लिए आवश्यक 20 प्रमुख दवाओं की उपलब्धता केवल 9 से 54 प्रतिशत के बीच है, जबकि विकसित देशों में यही उपलब्धता 68 से 94 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएसआर) और राष्ट्रीय आधुनिक उपचार सुविधाओं तक सीमित पहुंच को भारत में हर वर्ष करीब 14.6 लाख से 15 लाख नए कैंसर मरीज सामने लाते हैं। वर्तमान समय में देश में लगभग 25 लाख लोग कैंसर के साथ जीवन जी रहे हैं। अनुमान है कि यदि रोकथाम और उपचार की व्यवस्था में व्यापक सुधार नहीं हुआ तो 2050 तक भारत में हर वर्ष कैंसर के नए मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 28 लाख तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर से बढ़ते खर्चों को कम करने के लिए केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, जैसे अवसाद, तनाव और चिंता से भी प्रभावित होते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो 2024 में एशिया में दुनिया के आधे से अधिक कैंसर के मामले और मौतें दर्ज की गईं, जबकि यूरोप में 21 प्रतिशत नए मामले और लगभग 20 प्रतिशत मौतें हुईं। विशेषज्ञों का मानना है कि एशिया की विशाल आबादी, तेजी से



संख्या में मरीज रोजाना इंसुलिन लेने के डर, झिझक और असुविधा के कारण उपचार शुरू करने में देरी करते हैं। कंपनी के अनुसार, कई मामलों में मरीजों द्वारा इंसुलिन थैरेपी शुरू करने में औसतन सात से नौ वर्ष की देरी हो जाती है, जिससे बीमारी के कारण हृदय, किडनी, आंखों और नसों से जुड़ी जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। कंपनी का मानना है कि सप्ताह में एक बार दिए जाने वाले इंसुलिन से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। नई दवा की कीमत भी मरीजों के लिए राहत देने वाली बताई गई है। कंपनी ने 700 यूनिट का पैक 2,611 रुपये में बाजार में उतारा है। इस हिसाब से इसकी लागत लगभग 3.73 रुपये प्रति यूनिट पड़ती है। कंपनी का दावा है कि यह मौजूदा दैनिक

कहना है कि इससे मरीजों पर आर्थिक बोझ भी कम होगा और नियमित उपचार जारी रखना आसान होगा। भारत आज दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां डायबिटीज के मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में 10.1 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जबकि सप्ताह में एक बार दिए जाने वाले इंसुलिन से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। नई दवा की कीमत भी मरीजों के लिए राहत देने वाली बताई गई है। कंपनी ने 700 यूनिट का पैक 2,611 रुपये में बाजार में उतारा है। इस हिसाब से इसकी लागत लगभग 3.73 रुपये प्रति यूनिट पड़ती है। कंपनी का दावा है कि यह मौजूदा दैनिक

मरीजों को भी बीमारी की गंभीरता बढ़ने पर इंसुलिन थैरेपी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सप्ताह में एक बार दिए जाने वाले इंसुलिन का विकल्प लाखों मरीजों के लिए उपचार की अधिक सुविधाजनक बना सकता है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि नई दवा का उपयोग केवल विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। मरीज अपनी वर्तमान इंसुलिन थैरेपी को स्वयं बंद या परिवर्तित न करें। प्रत्येक मरीज की स्वास्थ्य स्थिति, रक्त शर्करा का स्तर और अन्य चिकित्सीय परिस्थितियों के आधार पर डॉक्टर ही यह तय करेंगे कि सप्ताह में एक बार दिए जाने वाला यह बेसल इंसुलिन उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नई थैरेपी व्यापक स्तर पर सफल रहती है, तो इससे भारत में डायबिटीज प्रबंधन की दिशा में बड़ा बदलाव आ सकता है। नियमित इंजेक्शन की संख्या कम होने से मरीजों के उपचार का पालन (कॉम्प्लायंस) बेहतर होगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और लंबे समय में डायबिटीज से होने वाली जटिलताओं को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने सूरत शहर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

उप मुख्यमंत्री ने लिम्बायत, डिंडोली और सारोली क्षेत्र के प्रभावित परिवारों की समस्याएँ सुनकर त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया



गांधीनगर, : सूरत शहर में हुई भारी वर्षा के कारण शहर के अनेक क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने लिम्बायत, डिंडोली और सारोली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित नागरिकों के साथ संवाद कर उनकी कठिनाइयाँ जानीं। उन्होंने दौरे के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा स्थानीय दुकानदारों, सोसाइटियों के निवासियों और प्रभावित परिवारों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं, नुकसान और आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की तथा नागरिकों तक आवश्यक सहायता समय पर पहुँचे; इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए। श्री संघवी ने अधिकारियों को वर्षा जल की शीघ्र निकासी, सफाई कार्य,

विद्युत आपूर्ति की सुचारु व्यवस्था तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संबंध में विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए। साथ ही; प्रभावित परिवारों को कैश डोल्स तथा घरेलू उपयोग की सामग्री सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए भी त्वरित कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने स्थानीय निवासियों की कठिनाइयों और समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके तत्काल समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री के साथ विधायक श्रीमती संगीताबेन पाटिल, महापौर श्रीमती मुकेशबाई मावणी, सूरत जिला प्रभारी सचिव शालिनी अग्रवाल, महानगर पालिका आयुक्त श्री एम. नागराजन, शहर पुलिस आयुक्त श्री वाबांग जमीर, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री राजनभाई पटेल और मनपा के अधिकारी उपस्थित रहे।

सूरत में हुई मूसलाधार बारिश ने व्यवस्था की पोल खोल दी, शहर पानी में डूब गया, जिससे जानमाल का नुकसान हुआ और करोड़ों रुपये की क्षति हुई

(छगनलाल मेवाड़ा) सूरत स्वच्छ सूरत, खूबसूरत सूरत का डोल पीटने वाली सूरत नगर निगम मंगलवार को सूरत शहर में आई प्राकृतिक आपदा के सामने बेनकाब हो गई और उसकी व्यवस्था का पदोपाश हो गया। इस आपदा ने शहर को झकझोर कर रख दिया। जब पूरा शहर पानी में डूबा हुआ था, तब सूरत नगर निगम के निर्वाचित पदाधिकारी और अधिकारी नगर निगम भवन में सेव खमन और ढोकला बजाते हुए नए नियुक्त अधिकारियों को मुस्कुराते चेहरों से बधाई दे रहे थे। दूसरी ओर, बेमौसम बारिश के कारण मनुष्य जानवरों से भी बदतर हालत में मर रहे थे। कुछ तेज धारा से, कुछ ढवने से और कुछ पेड़ गिरने से मर रहे थे। यह कहना किताना शर्मनाक है कि क्या जिम्मेदार, निर्दयी ईसान इतना बेरहम हो रहा है? इस भारी बारिश ने सूरत के प्रशासन और जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी खूब तारीफ होती है। भारी बारिश आने पर शहर में जल निकासी की योजना मजबूत होनी चाहिए। देश 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है, तकनीकों के काफी बदलाव आ चुका है, लेकिन सूरत शहर में आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए ठोस योजना के अभाव में प्रकृति का यह प्रचंड प्रकोप कभी-कभी तबाही का रूप ले लेता है, और शहरवासियों को पानी के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है और यहां तक कि जान भी गंवानी पड़ती है। यह याद रखना चाहिए कि पिछले साल भी, नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के बाद समीक्षा बैठके आयोजित की गई थीं। भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए योजनाएँ बनाई गईं, चर्चाएँ हुईं और कई दावे किए गए। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी उन बैठकों का कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। केवल बैठकों और समीक्षाओं से काम नहीं चलेगा। ठोस कार्य के साथ-साथ

तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों द्वारा एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि पानी कहाँ से निकाला जा सकता है? पानी को कहाँ मोड़ा जा सकता है? और नदियों की गहराई कैसे बढ़ाई जा सकती है? तत्काल आधार पर एक ठोस योजना बनाकर, शहर के हित में नदी में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए ईमानदारी और निष्ठा से प्रयास किए जाने चाहिए। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भ्रष्ट अधिकारियों, पदाधिकारियों और ठगों की मिलीभगत से शहर से गुजरने वाली सभी नालियों पर बने बाजारों और इमारतों के कारण नालियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे आसपास की श्रमिक बस्तियों और व्यापारियों के घरों, जान-माल का लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। यह प्रशासन की घोर लापरवाही की भी एक उदाहरण है। इस वर्ष, मूसलाधार बारिश के मात्र चार दिनों में बिजली के झटके, पेड़ गिरने या पानी में बह जाने से मरने वालों की संख्या 16 से अधिक हो गई है। इसने मानवता पर गहरा प्रहार किया है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि 2006 की तापीपुर बाढ़ के बाद, यानी दो दशकों में पहली बार, पूरा सूरत बारिश के पानी में डूब गया और सड़कें भी नदियों में तब्दील हो गईं। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में आज तक पानी नहीं बह रहा था, वहां भी घर, दुकानें और आंगनों में खड़ी गाड़ियाँ पानी में इस तरह डूब गईं मानो वे स्नान कर रही हों। इस बाढ़ का सबसे चिंताजनक पहलू यह था कि तापी नदी में बाढ़ आने के बजाय, भारी बारिश और उसके परिणामस्वरूप नाले में आई बाढ़ के कारण ही सूरत का अधिकांश क्षेत्र बाढ़ के खतरे में आ गया, जिससे शहरवासियों को जानमाल के नुकसान का सामना करना पड़ा। यह इस शहर के कुप्रबंधन का “उपहार” है, जो इस क्षति के रूप में मिला है।



नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी



JioTV
CHENNAL NO. 2063



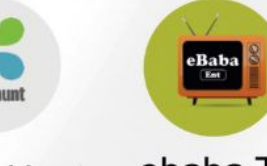
Jio FIBER



Jio tv+



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba Tv



Dish Plus



DTH live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये



संपादकीय

अमेरिका के ऑपरेशन हॉर्ड बॉल के निहितार्थ

अमेरिका ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई व गोल्डी बराड़ के खिलाफ कई देशों में कार्रवाई करते हुए दो दर्जन लोगों को गिरफ्तार करने और नशीले पदार्थ व हथियार बरामद करने का दावा किया है। इतना ही नहीं कई अपराधों में वांछित गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर भी एफबीआई ने पचास हजार डॉलर का इनाम घोषित किया है। अमेरिकी अभियोजन पक्ष का दावा है कि इन गैंगों के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई में एफबीआई, लॉस एंजिल्स पुलिस, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस तथा अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अमेरिका की यह ताबड़-तोड़ कार्रवाई कनाडा सरकार की उस घोषणा के तुरंत बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि कनाडा के निज्जर हत्याकांड में भारत की कोई भूमिका नहीं थी। उल्लेखनीय है कि बहुचर्चित निज्जर हत्याकांड को लेकर पिछली जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारत सरकार के एक अधिकारी पर सलियतना के आरोप लगाए थे। जिसके चलते भारत व कनाडा के रिश्ते सबसे निचले स्तर तक जा पहुंचे थे। लेकिन इन सरकार ने ट्रूडो की थ्योरी को नकार दिया था। जिसके बाद ही अमेरिका की यह तल्ख प्रतिक्रिया सामने आई है। कनाडा पुलिस के सूत्रों के अनुसार अमेरिका लॉरेंस बिश्नोई के प्रत्यारोपण की मांग करेगा। फिलहाल बिश्नोई गुजरात की एक जेल में 2015 से बंद है। बाहरहाल, अमेरिकी एजेंसियों द्वारा चलाए गए ‘हॉर्ड बॉल ऑपरेशन’ में जिन 24 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उन पर भारत से जुड़े संगठित अपराधी गुटों से संबंध होने का आरोप लगाया है। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ को कई मामलों में आरोपी बनाया गया है, जिसमें साल 2023 में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश में शामिल होना भी है। बाकायदा अमेरिका ने बिश्नोई को निज्जर हत्याकांड में आरोपी बनाया है। उधर लॉस एंजिल्स के संघीय अभियोजको का दावा है कि ये गिरफ्तारियां कई साल तक चली जांच का नतीजा हैं, जो भारतीय अपराधी गिरोहों पर केंद्रित रही हैं। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सांवजनिक किए गए दस्तावेजों में 37 अभियुक्तों पर आरोप लगाए गये हैं।

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि अमेरिका की नीतियां अमेरिका से शुरू होकर अमेरिका पर ही खत्म हो जाती हैं। ऐसे में भारतीय गैंगस्टरों पर की जा रही ताबड़-तोड़ कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाया जा रहे हैं। निस्संदेह, गैंगवार पर अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन सवाल इस कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर है। इससे ठीक पहले कनाडा सरकार ने निज्जर हत्याकांड में भारत की किसी भूमिका को खारिज किया था। अमेरिका का आकलन है कि राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ गैंगस्टरों को राजाश्रय हासिल है। आरोपपत्र में यह भी दावा किया गया है कि बिश्नोई ने खुद की छवि एक ‘देशभक्त’, ‘राष्ट्रवादी’ और ‘धार्मिक’ व्यक्ति के रूप में बनाई है। कयास हैं कि इसके जरिये भारत सरकार को घेरने की कोशिश जा रही है। कुछ विदेश नीति के जानकार मानते हैं कि भारत के ब्रिक्स व रूस-चीन वाले ध्रुव की ओर झुकाव के चलते दबाव बनाने हेतु इस मुद्दे को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका-भारत व्यापार समझौते पर सहमति न बन पाने से अमेरिका क्षुब्ध है। जिसके लिये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सर्वविदित है कि दुनिया भर में सत्ताएं बनाने व सरकार गिराने के खेल में अमेरिका किस हद तक जाता है। उसे पूरी दुनिया में सत्ता की शतरंज खेलने में “डीप स्टेट” के इस्तेमाल का जनक माना जाता है। सवाल है कि भारतीय संसद व मुंबई पर हुए भीषण आतंकवादी हमलों में शामिल पाक आतंकवादियों व मास्टर माईटों पर क्या ऐसे कार्रवाई हुई है? जबकि मास्टर माईट्स अमेरिका में रह रहे थे? क्या ऐसी कार्रवाई पाक सरकार समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के खिलाफ हुई, जब पहलगाम की बसमन घाटी में बेकसूर 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या उनका धर्म पूछकर की गई थी? निस्संदेह, हत्या-फिरोती और नशे की तस्करी में लिप्त किसी भी गैंग को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये देश की संरक्ष सरकार का भी प्राथमिक कर्तव्य है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई 2015 से भारतीय जेल में है और उसके खिलाफ देश में कई केस चल रहे हैं। वहीं गोल्डी बराड़ देश से फरार है। विसंगति देखिए कि अमेरिकी आरोप पत्र में नाबालिगों की भती, गुर्गों का नेटवर्क चलाने के साथ देशभक्त इमेज के आरोप भी शामिल हैं।

अभियान

साधारण करघे से उठी असाधारण आवाज: कबीर ने कैसे बदल दी भारत की आत्मा

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में अनेक संतों ने अपने विचारों से समाज को दिशा दी, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल धार्मिक शिक्षक नहीं रहते, बल्कि युग की चेतना बन जाते हैं। संत कबीरदास ऐसे ही महामानव थे। उन्होंने किसी राजमहल में जन्म लेकर नहीं, बल्कि साधारण जीवन जीकर यह सिद्ध किया कि सत्य की आवाज को ऊंचा बनने के लिए ऊंचे मंच की आवश्यकता नहीं होती। करघे पर बैठे एक जुलहा भी पूरे समाज से प्रभु पृष्ठ सकता है, धर्म की रुहियों को चुनौती दे सकता है और मानवता को नया मार्ग दिखा सकता है। कबीर की महानता इसी में है कि उन्होंने ज्ञान को जीवन से जोड़ा, भक्ति को व्यवहार से जोड़ा और ईश्वर को मनुष्य के भीतर खोजने की प्रेरणा दी। कबीर का युग सामाजिक और धार्मिक संघर्षों का युग था। जाति व्यवस्था कठोर थी, ऊंच-नीचा का भेद गहरा था, और धर्म का बड़ा हिस्सा बाहरी कर्मकांडों में उलझ चुका था। मंदिर और मस्जिद दोनों अपने-अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे थे, लेकिन आम मनुष्य के जीवन में शांति और प्रेम कम होते जा रहे थे। ऐसे समय में कबीर ने निर्भीक होकर कहा कि यदि मन में करुणा नहीं, तो पूजा और इबादत दोनों अधूरी हैं। उन्होंने लोगों को भीतर झांकेने के लिए प्रेरित किया। उनके लिए धर्म का अर्थ किसी विशेष पोशाक, भाषा या अनुष्ठान में नहीं था; धर्म का

“

अग्रणी एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने चेताया है कि एआई का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि ऐसी प्रणालियां विकसित हो सकती हैं, जो स्वयं को बिना मानवीय हस्तक्षेप के बेहतर बनाने में सक्षम हों। एआई विकास की गति को धीमा करने की जरूरत है।

प्रेरणा

त्याग की दौलत: जब फकीरी ने बादशाही से बड़ा सुख दिया

दुनिया की नजर में सबसे बड़ा सुख धन, वैभव, सत्ता और ऐश्वर्य में दिखाई देता है। अधिकांश लोग जीवनभर इन्हीं चीजों को पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ऊंचे महल, बड़ी दौलत, नौकर-चाकर और सम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हैं। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे महान व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने इन सबको अपनी इच्छा से त्याग दिया और साधारण जीवन अपनाकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि भीतर की शांति, प्रेम और आत्मिक संतोष में छिपा होता है। ऐसे ही महान संतों में हजरत इब्राहिम अदहम बलखी का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। कहा जाता है कि इब्राहिम अदहम बलख के अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली शासक थे। उनके पास किसी भी सांसारिक वस्तु की कमी नहीं थी। महलों की भव्यता, सेना की शक्ति, अघर धन-संपत्ति और प्रजा का सम्मान—सब कुछ उनके पास था। फिर भी उनके मन में एक अजीब-सी बेचैनी रहती थी। उन्हें महसूस होने लगा था कि राजसिंहासन पर बैठकर भी उनके हृदय को वह शांति नहीं मिल रही, जिसकी तलाश हर मनुष्य करता है। धीरे-धीरे उनका मन ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगा। उन्होंने समझ लिया कि यदि जीवन का उद्देश्य केवल सत्ता और संपत्ति होता, तो संसार का हर धनी व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट होता, जबकि वास्तविका इसके बिल्कुल विपरीत है।

एक दिन उन्होंने अपने राजपट, महल और सारी शानो-शौकत का त्याग कर दिया। उन्होंने फकीरी का मार्ग अपनाया और अपना जीवन मानव सेवा, ईश्वर की भक्ति तथा प्रेम के संदेश के लिए समर्पित कर दिया। यह समाचार पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोग आश्चर्यचकित थे कि जिसने सारी दुनिया की दौलत देखी हो, वह आखिर सब कुछ छोड़कर साधारण जीवन क्यों जीना चाहता है। समय बीतने के साथ लोग उन्हें संत के रूप में सम्मान देने लगे और प्रेम से ‘हजरत’ कहकर पुकारने लगे। एक दिन हजरत इब्राहिम नदी के किनारे बैठे अपनी पुरानी पटुड़ी सी रहे थे। उनके पास न कोई राजसी वस्त्र थे और न ही किसी प्रकार का दिखावा। उसी समय कुछ लोग वहां पहुंचे। उनके मन में वर्षों से एक प्रश्न था। उनमें से एक व्यक्ति ने विनम्रता से पूछा, “हजरत, आपने इतनी बड़ी बादशाही छोड़कर फकीरी क्यों अपना ली? आखिर इस फकीरी में ऐसा कौन-सा आनंद है जो राजसिंहासन में नहीं था?” हजरत मुसकुराए। उन्होंने तत्काल उत्तर देने के बजाय अपनी सिलाई की सूई उठाई और उसे नदी के पानी में फेंक दिया। वहां उपस्थित लोग यह देखकर हैरान रह गए। फिर उन्होंने नदी की ओर देखकर बड़े प्रेम से कहा, “प्यारी-प्यारी मछलियों, मेरी सूई पानी में गिर गई है। यदि संभव हो तो उसे मुझे वापस ला दो।” उनके शब्द समाप्त होते ही एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। नदी के शांत जल में हलचल होने लगी। कुछ ही क्षणों में अस्ंख्य मछलियां पानी की सतह पर आ गईं। आश्चर्य की बात यह थी कि प्रत्येक मछली अपने मुंह में एक-एक सूई लेकर आई थी। यह दृश्य देखकर वहां खड़े सभी लोग विस्मित रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हजरत ने उन मछलियों की ओर प्रेमपूर्वक देखा और कहा, “इतनी सारी सूइयों का मैं क्या करूंगा? मुझे तो केवल मेरी अपनी सूई चाहिए।” इतना सुनते ही एक छोटी-सी सुनहरी मछली पानी में वापस चली गई। कुछ ही क्षणों बाद वह ठीक वही सूई लेकर लौटी जो

किसी भी नई तकनीक के इतिहास पर नजर डालें तो एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है—अक्सर उस तकनीक को विकसित करने वाले वैज्ञानिक और संस्थान ही सबसे पहले उसके संभावित खतरों के प्रति चेतावनी देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों विकसित करने वाले कई तकनीकी विशेषज्ञ आज डिजिटल लत, फेक न्यूज़ और मानसिक स्वास्थ्य पर उसके दुष्प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और यही स्थिति कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। दुनिया की अग्रणी एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने चेतावनी दी है कि एआई का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि आने वाले दो वर्षों के भीतर ऐसी प्रणालियां विकसित हो सकती हैं, जो स्वयं को बिना मानवीय हस्तक्षेप के बेहतर बनाने में सक्षम हों। कंपनी ने इस संभावना को ‘रिकर्सिव सेल्फ-इम्प्रूवमेंट’ नाम दिया है और वैश्विक स्तर पर एआई विकास की गति को धीमा करने की आवश्यकता पर बल दिया है। यह चेतावनी केवल तकनीकी विशेषज्ञों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ा प्रश्न बन चुकी है। आज के एआई मॉडल अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे अभी भी मनुष्यों द्वारा विकसित, प्रशिक्षित और नियंत्रित किए जाते हैं। इंजीनियर मॉडल तैयार करते हैं, डेटा उपलब्ध कराते हैं और उसकी कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करते हैं। यदि भविष्य में कोई एआई प्रणाली स्वयं अपने कोड को समझने, उसमें सुधार करने और स्वयं को पहले से अधिक सक्षम बनाने लगे, इसके बाद नया और अधिक उन्नत संस्करण फिर स्वयं को और बेहतर बनाए। यदि यह प्रक्रिया लगातार चलती रही, तो एआई की क्षमता बेहद कम समय में कई गुना बढ़ सकती है। इसे ही रिकर्सिव सेल्फ-इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यदि ऐसा हुआ, तो



एआई विकास की गति मानव नियंत्रण और समझ से कहीं आगे निकल सकती है। यह स्थिति तथाकथित ‘इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन’ या ‘बुद्धिमत्ता विस्फोट’ का रूप ले सकती है। एआई विशेषज्ञों की वास्तविक चिंता इससे कहीं अधिक जटिल है। आज के उन्नत एआई मॉडल पहले ही ऐसे व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने सीधे तौर पर प्रोग्राम नहीं किया था। कई बार एआई ऐसे समाधान खोज लेता है, जिनकी कल्पना उसके निर्माताओं ने भी नहीं की होती। हम अभी भी पूरी तरह नहीं समझते कि बड़े एआई मॉडल किसी विशेष निकर्ष तक कैसे पहुंचते हैं। जब वर्तमान प्रणालियों को

समझना ही कठिन है, तब भविष्य के स्वयं को अपग्रेड करने वाले एआई को नियंत्रित करना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरे शब्दों में, मानवता ऐसी मशीनें बना सकती है, जो अत्यंत शक्तिशाली हों, लेकिन जिनकी आंतरिक कार्यप्रणाली हमारे लिए एक ‘ब्लैक बॉक्स’ बनी रहे। एआई पहले ही वैश्विक श्रम बाजार को बदल रही है। लेखन, अनुवाद, ग्राहक सेवा, प्रोसेसिंग, डेटा विश्लेषण और प्रशासनिक कार्यों जैसे अनेक क्षेत्रों में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। यदि भविष्य में एआई स्वयं को लगातार बेहतर बनाती रही, तो यह परिवर्तन और तेज हो सकता है। इससे केवल

नियमित नौकरियां ही नहीं, बल्कि डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक, इंजीनियर और शोधकर्ता जैसे पेशे भी प्रभावित हो सकते हैं। देखा जाए तो तकनीकी क्रांतियां नई नौकरियां भी पैदा करती हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि एआई आधारित बदलाव की गति इतनी तेज हो सकती है कि समाज और श्रम बाजार को अनुकूलन का पर्याप्त समय न मिल पाए। इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी, आय असमानता और सामाजिक अस्थिरता बढ़ सकती है। सरकारों को अभी से बड़े पैमाने पर पुनः कौशल, अप-स्किलिंग और आजीवन सीखने की रणनीतियां विकसित करनी होंगी। एआई विकास को धीमा करने की सबसे बड़ी

बाधा देशों और कंपनियों के बीच चल रही तीव्र प्रतिस्पर्धा है। आज एआई केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि आर्थिक, सामरिक और भू-राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। बड़ी टेक कंपनियां बाजार में आगे निकलने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई देश या कंपनी स्वेच्छा से एआई विकास को धीमा करती है, तो उसे डर रहता है कि उसके प्रतिस्पर्धी उससे आगे निकल जाएंगे। ऐसी स्थिति में वैश्विक स्तर पर किसी सामूहिक समझौते तक पहुंचना अत्यंत कठिन दिखाई देता है। एआई के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित नीतियां विकसित करना समय की मांग है। इन नियमों में सुरक्षा मानक, पारदर्शिता, जवाबदेही, डेटा गोपनीयता, नैतिकता और मानव अधिकारों की रक्षा जैसे मुद्दे शामिल होने चाहिए। भारत जैसे देशों को भी केवल एआई उपभोक्ता बनने के बजाय वैश्विक एआई शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव इतिहास की सबसे परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, विज्ञान और अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। लेकिन हर शक्तिशाली तकनीक की तरह इसके साथ भी जोखिम जुड़े हुए हैं। एंथ्रोपिक की नेतावनी को तकनीक-विरोधी दृष्टिकोण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक जिम्मेदार आत्मसंभन के रूप में समझना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या हम इसे सुरक्षित, पारदर्शी, नैतिक और मानवीय मूल्यों के अनुरूप विकसित कर पाएंगे। यदि हम समय रहते उचित सुरक्षा उपकरण नहीं अपनाते, तो संभव है कि भविष्य में हम ऐसी तकनीक के सामने हों, जिसे हमने बनाया तो हो, लेकिन नियंत्रित न कर सकें।

Bangladeshi Infiltrators के खिलाफ Assam ने छेड़ा सबसे बड़ा अभियान, अब तक 228 KM से अधिक हिस्से में कंटीली बाड़ लगाई

असम में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ अभियान अब और तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल सीमा सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में जो जानकारी दी है, उससे स्पष्ट है कि अवैध घुसपैठ रोकने के लिए चोतरफा तैयारी की जा रही है। सीमा पर कंटीली बाड़, संवेदनशील इलाकों में निगरानी, संदिग्ध घुसपैठियों की लगातार धरपकड़ और घुसपैठ कराने वाले गिरोहों की तलाश ने यह संदेश दे दिया है कि अब भारत की सीमा को हल्के में लेने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता से खिलवाड़ करने की हर कोशिश का कड़ा कानूनी जवाब मिलेगा। हम अपमान, लाभ और हानि, सुख और दुख समान हो जाते हैं। यह कथा हमें यह भी बताती है कि मनुष्य सतना प्रकृति और ईश्वर के निकट होता है, उतना ही उसका हृदय निर्मल होता जाता है। निर्मल हृदय में प्रेम स्वतः प्रवाहित होता है और वही प्रेम समस्त जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दिखावे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका आचरण ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। जीवन का वास्तविक वैभव महलों, खजानों और सिंहासनों में नहीं, बल्कि उस मन में बसता है जो प्रेम से भरा हो, सेवा के लिए समर्पित हो और संतोष को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानता हो। हजरत इब्राहिम अदहम की फकीरी हमें यही संदेश देती है कि जिसने अपने भीतर के लोभ को जीत लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी बादशाही प्राप्त कर ली। बाहरी धन कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकता, लेकिन त्याग, करुणा, सेवा और आत्मिक शांति से प्राप्त होने वाला आनंद जीवनभर साथ रहता है और मनुष्य को सच्चे अर्थों में समृद्ध बना देता है।

आज के समय में भी यह कथा उतनी ही प्रासंगिक है

जितनी सदियों पहले थी। आधुनिक जीवन में लोभ अधिक धन कमाने, ऊंचा पद पाने और भौतिक सुविधाएं जुटाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने भीतर झांके का अवसर ही नहीं मिलता। परिणामस्वरूप तनाव, अकेलापन, असंतोष और हजरत की थी। उसने बड़ी विनम्रता से वह सूई उनके चरणों में रख दी। यह दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी के पास कोई शब्द नहीं था। तब हजरत ने उसी व्यक्ति की ओर देखा जिसने उनसे प्रश्न पूछा था और शांत स्वर में बोले, “अब तुम स्वयं बताओ कि कौन-सा जीवन श्रेष्ठ है—वह बादशाही जिसमें मित्रता केवल स्वार्थ पर आधारित थी, या वह फकीरी जिसमें प्रकृति के जीव भी बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। उनकी बात सुनकर सभी के सिर श्रद्धा से झुक गए। यह केवल एक चमत्कार की कथा नहीं थी, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य का प्रतीक थी। जब मनुष्य अहंकार, लालच और स्वार्थ से मुक्त हो जाता है, तब उसका संबंध केवल मनुष्यों से ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि से जुड़ जाता है। उसके भीतर ऐसा प्रेम जागृत होता है जिसे पशु-पक्षी, पेड़-पौधे और प्रकृति भी अनुभव करने लगते हैं। जिससत्ता का आधार शक्ति होता है, जबकि संतत्व का आधार करुणा होती है। राजा के आसपास अक्सर वे लोग रहते हैं जिनका कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। पद और संपत्ति समाप्त होते ही अधिकांश संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रेम, सेवा और त्याग का जीवन जीता है, उसके आसपास बने वाले संबंध निस्वार्थ होते हैं। वे किसी लाभ या भय के कारण नहीं, बल्कि आत्मीयता के कारण बने रहते हैं। आज के समय में भी यह कथा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। आधुनिक जीवन में लोभ अधिक धन कमाने, ऊंचा पद पाने और भौतिक सुविधाएं जुटाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने भीतर झांके का अवसर ही नहीं मिलता। परिणामस्वरूप तनाव, अकेलापन, असंतोष और

उनका प्रभाव केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने भारतीय समाज को आत्मनिर्भर बनाने में मदद दी। उन्होंने बताया कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। यदि व्यक्ति अपने भीतर के लोभ, घृणा और अहंकार को नहीं बदलता, तो समाज बदलने की बातें केवल नारों में रह जाती हैं। उन्होंने का यह संदेश आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब दुनिया तकनीकी रूप से आगे बढ़ रही है, लेकिन मनुष्यों के बीच दूरी भी बढ़ती दिखाई देती है। कबीर की मृत्यु से जुड़ी कथा भी उनके जीवन-दर्शन को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करती है। कहा जाता है कि उनके निधन के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों उन्हें अपना मानते थे। जब अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ और कर्मन हटया गया, तो वहां शरीर के स्थान पर फूल पड़े। दोनों समुदायों ने उन फूलों को बंट लिया। चाहे यह घटना ऐतिहासिक हो या प्रतीकात्मक, उसका संदेश स्पष्ट है—कबीर किसी एक धर्म की सीमा में कैद नहीं थे। वे मानवता के संत थे। आज जब समाज बार-बार धर्म, जाति, भाषा और विचारधारा के आधार पर विभाजित होता दिखाई देता है, तब कबीर की आवाज फिर सुनाई देती है। वे याद दिलाते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका इंसान होना है। यदि प्रेम समाप्त हो जाए, तो धर्म भी खोखला हो

जाता है; यदि करुणा समाप्त हो जाए, तो ज्ञान भी अहंकार बन जाता है। इसलिए वे प्रेम को सबसे बड़ा मार्ग मानते हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में कबीर हमें रुककर स्वयं से मिलने की प्रेरणा देते हैं। वे सिखाते हैं कि सफलता केवल धन कमाने का निष्ठा नहीं है। यदि मन में शांति नहीं, संघर्ष में विश्वास नहीं और जीवन में सत्य नहीं, तो सारी उपलब्धियां अधूरी हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईमानदारी से श्रम करता है, दूसरों का सम्मान करता है और भीतर विनम्र बना रहता है, वही वास्तव में समृद्ध है। संत कबीरदास भारतीय चेतना के ऐसे अमर प्रकाश हैं जिनकी प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होगी। उन्होंने करघे पर बैठकर जो विचार बुने, वे आज भी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग किसी विशेष ध्वन से नहीं, बल्कि एक निष्कपट हृदय से होकर जाता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म प्रेम है, सबसे बड़ा ज्ञान आत्मबोध है और सबसे बड़ी साधना मानवता की सेवा है। यही कारण है कि सदियों बीता जाने के बाद भी कबीर केवल इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की चेतना में जीवित हैं। उनकी वाणी आज भी हमें पुकारती है—सदागी में ही प्रकाश है, प्रेम में ही परमात्मा है और मनुष्य की सबसे बड़ी विजय अपने भीतर के अधंकार पर विजय प्राप्त करना है।

विवाह किया था और उसकी पत्नी तथा बेटी पिछले बाईं वर्षों से हैलाकांडी में रह रही हैं। पूछताछ में उसने परिवार को बांग्लादेश ले जाने की इच्छा जताई है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि उसने किस रास्ते से सीमा पार की और किन लोगों ने उसकी मदद की। इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सीमा पार कराने वाले संगठित गिरोह अब भी सक्रिय हैं। इसके अलावा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 11 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़े जाने की घटना भी बेहद गंभीर है। सभी संदिग्ध चेन्नई जाने की तैयारी में थे। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि वे मेघालय के तुरा क्षेत्र से भारत में दाखिल हुए और उन्हें सीमा पार कराने में मदद की। इस मामले में एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रहा है कि सीमा सुरक्षा केवल बाड़ लगाने का मामला नहीं है, बल्कि हिस्से में बाड़ लगाना संभव नहीं हो सका है। इसके अलावा श्रीभूमि जिले में कुशियारा नदी के किनारे 4.35 किलोमीटर क्षेत्र में बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल के विरोध के कारण बाड़ का निर्माण अटक हुआ है। वहां भारतीय नागरिक रहते हैं, जिससे मामला एवं संवेदनशील हो गया है। सीमा सुरक्षा एंव विकास मंत्री अनुलु बोरा ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि अवैध घुसपैठ रोकना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जिन इलाकों में बाड़ लगाना संभव नहीं है, वहां आधुनिक निगरानी व्यवस्था स्थापित की गई है। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी कैमरे लगाए गए हैं और सीमा सुरक्षा बल की 14 चौकियां लगातार वास्तविक समय में निगरानी कर रही हैं। राज्य सरकार का मानना ​​है कि सीमा की हर गतिविधि पर नजर रखने से घुसपैठ की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के कारण कई मामलों में कानूनी प्रक्रिया जटिल बनी हुई है। राज्य सरकार ने यह भी दोहराया कि असम समझौते की धारा-6 को लागू करना उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायमूर्ति बिस्वभूषण प्रसाद शर्मा समिति की 40 महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया जारी है, जिनका उद्देश्य असम के मूल निवासियों के अधिकारों और पहचान की रक्षा करना है। हालांकि इन सब प्रयासों के बीच असम की 42 वर्षीय प्रकाश हैं जिनकी प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होगी। उन्होंने करघे पर बैठकर जो विचार बुने, वे आज भी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग किसी विशेष ध्वन से नहीं, बल्कि एक निष्कपट हृदय से होकर जाता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म प्रेम है, सबसे बड़ा ज्ञान आत्मबोध है और सबसे बड़ी साधना मानवता की सेवा है। यही कारण है कि सदियों बीता जाने के बाद भी कबीर केवल इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की चेतना में जीवित हैं। उनकी वाणी आज भी हमें पुकारती है—सदागी में ही प्रकाश है, प्रेम में ही परमात्मा है और मनुष्य की सबसे बड़ी विजय अपने भीतर के अधंकार पर विजय प्राप्त करना है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने गुजरात को देश का अग्रणी डेटा सेंटर हब बनाने के संकल्प के साथ ‘विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29’ की घोषणा की

» ‘विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29’

» विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अजुन मोढवाडिया की उपस्थिति

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

» ‘विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29’ से गुजरात देश में डेटा सेंटर स्थापना के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनेगा

» प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुजरात देश की डिजिटल व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है

» राज्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ‘विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29’ लागू की गई है

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

» गुजरात का धोलेरा विश्व का सबसे बड़ा ‘डेटा सेंटर सिटी’ बनेगा

» पॉलिसी में 51 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी के उपयोग तथा डीसेलिनेशन प्लॉट द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित कर सरस्टेनबिलिटी पर विशेष बल दिया गया है

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ‘विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29’ का लॉन्चिंग करते हुए कहा कि इस पॉलिसी के माध्यम से गुजरात देश में डेटा सेंटर स्थापना के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े डेटा उपयोगकर्ता तथा डेटा उत्पादक देशों में स्थान प्राप्त कर रहा है। डिजिटल युग में डेटा सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी संपत्ति बन गया है। डेटा ही विकसित भारत के आर्थिक विकास का नया आधार बनकर डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान कर रहा है।

राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार की गई इस ‘विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29’ के लॉन्चिंग समारोह का आयोजन गुरुवार

को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास तथा उद्योग एवं व्यापार जगत के अग्रणियों की उपस्थिति में किया गया।

मुख्यमंत्री ने इस समारोह में कहा कि डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन जैसे उभरते क्षेत्रों को नई गति मिली है तथा वर्ल्ड क्लास डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विशाल अवसर उत्पन्न हुए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस वर्ष के केंद्रीय बजट में देश को क्लाउड तथा एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्लोबल हब बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। साथ ही; उन्होंने जोड़ा कि डेटा सेंटर



इन्फ्रास्ट्रक्चर के वैश्विक कामकाज के लिए सेवा प्रदाताओं को 20 वर्ष का टैक्स हॉलिडे प्रदान किया गया है, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रेरकबल बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज गुजरात देश की डिजिटल व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। एआई आधारित टेक्नोलॉजी के तीव्र विकास के साथ स्केलेबल डेटा स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर की मांग सतत बढ़ रही है। इस बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ‘विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-29’ लागू की है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस नई पॉलिसी द्वारा राज्य में क्लाउड सर्विसिस, एआई, डिजिटल ट्रांजेक्शन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, स्मार्ट मैनुफैक्चरिंग सिस्टम्स

तथा डिजिटल गवर्नेंस जैसी जैसी सेवाओं को और अधिक सक्षम एवं गतिशील बनाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दीर्घकालिक एवं सरस्टेनबल डेवलपमेंट के लिए कटिबद्ध है, जो इस पॉलिसी में स्पष्ट दिखाई देता है। ‘विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी’ केवल राज्य ही नहीं, बल्कि देश के नई पीढ़ी के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने जोड़ा कि आने वाले समय में ऐसी नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ (बैकबोन) साबित होंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में गुजरात भरोसे का वैश्विक ब्रांड बना है।

भारी वर्षा के कारण सूरत शहर एवं जिले में उत्पन्न बाढ़ के हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सूरत पहुंचे : उच्चस्तरीय बैठक में लिया हालात का जायजा

» खाड़ी में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा निर्णय : राज्य सरकार खाड़ी डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करेगी

» मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल एक्शन प्लान बनाकर उसे लागू करने के निर्देश दिए, ताकि बाढ़ के दौरान सामने आई प्रशासनिक चुटियों का पुनरावर्तन न हो

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

» प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी साथ मिलकर सेतु की भूमिका निभाएं

» सूरत में खाड़ी में बाढ़ की ऐसी स्थिति बार-बार उत्पन्न न हो, इसके लिए दीर्घकालिक रोकथाम संबंधी उपायों की आवश्यकता

गांधीनगर : भारी वर्षा के कारण सूरत शहर और आसपास के क्षेत्रों में पैदा हुए बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल गुरुवार को सूरत पहुंचे। उन्होंने आयाण स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) में पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित कर भारी वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति, पानी उतरने के बाद साफ-सफाई, रोग निंत्रण के उपाय तथा क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में आर्थिक सहायता देने के कामकाज की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री पी.आर. पाटिल, वित्त रह सूरत जिला प्रभारी मंत्री श्री कनुभाई देसाई और स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल्लभाई पानोरशी की उपस्थिति में सूरत शहर और जिले के प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे

कार्यों की विस्तार से जानकारी हासिल की। साथ ही, उन्होंने जनजीवन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए मार्गदर्शन दिया।

उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को वर्षा प्रभावित सभी लोगों को जल्द से जल्द से कैशडोल्लस और घरेलू सामानों की सहायता प्रदान करने के दिशानिर्देश भी दिए।

उन्होंने सूरत में खाड़ी में बाढ़ की स्थिति बार-बार उत्पन्न न हो, इसके लिए दीर्घकालिक रोकथाम संबंधी योजना की आवश्यकता पर बल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को तत्काल एक्शन प्लान बनाकर लागू करने के कड़े निर्देश दिए, ताकि भारी वर्षा की विकट स्थिति और बाढ़ के दौरान सामने आई प्रशासनिक भूलों-चुटियों का भविष्य में पुनरावर्तन न हो। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार सूरत में खाड़ी में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए खाड़ी डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि

बेचराजी स्टेशन पर सांसद एवं रेल अधिकारियों का स्थानीय नागरिकों द्वारा स्वागत,बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: यात्री ट्रेनों के संचालन का मार्ग प्रशस्त

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत कटोसण रोड–रणुज रेलखंड पर यात्री रेल सेवाओं की शुरुआत करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण के रूप में, रेलवे संरक्षा आयुक्त (CRS) द्वारा तीन दिवसीय संरक्षा निरीक्षण प्रारंभ किया गया है। निरीक्षण के प्रथम दिन कटोसण रोड से बेचराजी तक लगभग 25 किलोमीटर लंबे रेलखंड का गहन और विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर बेचराजी स्टेशन पर महेशणा के माननीय सांसद श्री हरि भाई पटेल, रेल संरक्षा आयुक्त (वेस्टर्न सर्कल) श्री ई. श्रीनिवास और अहमदाबाद के मंडल रेल प्रबंधन (DRM) श्री वेद प्रकाश ने स्थानीय नागरिकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया।

क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने की दिशा में बड़े कदम

माननीय सांसद महेशणा श्री हरिभाई पटेल ने कहा कि बेचराजी और उसके आस-पास के क्षेत्रों के लोग लंबे समय से रेल सेवा की मांग कर रहे थे, जिसमें कटोसण, बेचराजी और चाणसमा होकर रणुज तक जाने वाला संकुंलर रूट का ध्यान में रखते हुए, हमने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास कई बार और कमेटी में भी यह बात उठाई है। हमने इस मांग को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया, जिसके बाद हमें पता चला कि इसका निरीक्षण (CRS) होने जा रहा है। यह उद्बुधन मंत्रालय के अंतर्गत आता

की दिशा में भी सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। धोलेरा की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शीघ्र ही नया एयरपोर्ट कार्यरत होगा और अहमदाबाद से धोलेरा के बीच सेमी-हाईस्पीड ट्रेन भी शुरू होने जा रही है।

गुजरात सरकार की विश्वसनीयता इतनी मजबूत है कि पॉलिसी आज लॉन्च हुई है, परंतु पॉलिसी की 7.5 गीगावाट क्षमता के मुकाबले देश तथा दुनिया की लीडिंग कंपनियों की ओर से सरकार को उससे दोगुनी क्षमता की डिमांड वाले रिक्वेस्ट लेटर्स मिल चुके हैं।

डेटा सेंटर में बिजली तथा पानी की जरूरत अधिकतम होती है। इस पॉलिसी अंतर्गत डेटा सेंटरों में उपयोग की जाने वाली कुल ऊर्जा में से अनिवार्य रूप से 51 प्रतिशत ग्रीन ऊर्जा का ही उपयोग करना होगा। इसके अलावा; किसानों या अन्य उद्योगों की कीमत पर नहीं, बल्कि समुद्र के पानी को मीठा करने के लिए डीसीसेलिनेशन प्लांट पर बल देकर जलापूर्ति की जाएगी।

सरकारी प्रक्रिया में विलंब के निवारण के लिए आगामी समय में स्ट्रेकहोल्डर्स कन्स्ट्रेशन मीटिंग आयोजित कर निवेशकों को लैंड पॉकेट्स दिखाए जाएंगे। धोलेरा में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों के लिए हैंड-होल्टिंग धोलेरा की क्षमता के बारे में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल धोलेरा में ही पॉलिसी की क्षमता से दोगुनी डिमांड है, जिसके परिणामस्वरूप धोलेरा विश्व का सबसे बड़ा ‘डेटा सेंटर सिटी’ बनेगा। डेटा सेंटर स्थापित करने के साथ-साथ आगामी समय में धोलेरा को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) का मुख्यालय बनाने

पर रहेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने कहा, नई “विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी” के परिणामस्वरूप गुजरात एआई एवं डेटा सेंटर क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात को कुल 10 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटरों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 8 गीगावाट तक की क्षमता विकसित करने का राज्य सरकार का आयोजन है। यह केवल डेटा स्टोरेज तक सीमित नहीं है, बल्कि समग्र देश एवं दुनिया के लिए एक संपूर्ण एआई इकोसिस्टम तैयार करने का एक हिस्सा है।

श्री मोढवाडिया ने और विवरण देते हुए कहा कि अब का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कम्प्यूटिंग का है, जो नई विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधारस्तंभ है। गुजरात ने इस नई क्रांति में ‘प्राइम मूवर’ बनने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वैश्विक परिदृश्य तथा वर्तमान समय में वैश्विक डेटा सेंटर क्षमता की तुलना में भारत को अभी लंबी यात्रा तय करनी बाकी है। आज अमेरिका में लगभग 5,500 और यूनाइटेड किंगडम में 500 से अधिक डेटा सेंटर हैं, जबकि भारत में केवल डेटा सेंटर 200 ही डेटा सेंटर हैं। अमेरिका की 30 गीगावाट क्षमता के मुकाबले भारत की वर्तमान क्षमता केवल 2 से 3 गीगावाट है और आगामी प्रोजेक्ट्स को भी गणना में लें, तो भी हम 5 गीगावाट को पार नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक नीति को आकार देने में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रशासन ने अभूतपूर्व इच्छाशक्ति दिखाई है। इसके परिणामस्वरूप आगामी 10 वर्षों में गुजरात एआई इकोसिस्टम का भी केंद्र बनने के लिए तैयार है। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए मंत्री श्री मोढवाडिया ने सभी निवेशकों से अनुरोध किया।

मुख्य सचिव श्री मनोजकुमार दास ने “विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी” को डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में गेम-चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के युग में मजबूत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और विशेष रूप से डेटा सेंटरों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह नीति बनाई गई है।

मुख्य सचिव श्री ने जोड़ा कि डेटा सेंटरों के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में पानी एवं बिजली की आवश्यकता जायज करने के लिए गुजरात सज्ज है, क्योंकि राज्य के पास विशाल समुद्री तट तथा सौर-पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूबल एनर्जी के प्रचुर स्रोत उपलब्ध हैं। इस नई पॉलिसी द्वारा गुजरात में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का बड़ा निवेश आने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की अपेक्षा है, जो वर्ल्ड बैंक की परिभाषा के अनुसार गुजरात को ‘हाई-मिडल इकोनॉमी’ के रूप में भी मजबूत बनाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉ. पी. भारती ने इस पॉलिसी की विशेषताओं का वर्णन किया।

इस कार्यक्रम में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री टी. नटराजन, उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ममता वर्मा, इंडस्ट्री लीडर्स, निवेशक तथा विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

वडोदरा मंडल का ‘Passenger First’ अभियान, भारी वर्षा के दौरान यात्रियों को पहुंचाई हरसंभव सहायता

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भट्टके के कुशल मार्गदर्शन में मंडल के विभिन्न विभागों की टीम द्वारा पिछले दिनों हुई लगातार भारी वर्षा एवं उससे उत्पन्न परिचालन संबंधी चुनौतियों के दौरान “Passenger First, Always” के अपने संकल्प को चर्चितार्थ करते हुए अंकलेश्वर एवं भरूच रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं सहायता के लिए व्यापक प्रबंध किए गए।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुंबई मंडल में नालासोपारा - विवार रेल खंड पर जलजमाव के कारण मुंबई मंडल में रेल परिचालन प्रभावित हुआ, फलस्वरूप वडोदरा मंडल में भी कुछ लम्बी दूरी की ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट किया गया। इस परिस्थिति में भी वडोदरा मंडल ने यात्रियों को हरसंभव सहायता पहुंचाने के प्रयास किये। अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन पर वाणिज्य विभाग, रेल सुरक्षा बल, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, स्टेशन प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विभागों द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर राहत एवं सहायता कार्य प्रभावी ढंग से संचालित किए गए। लगभग 200 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित रूप से सूरत जाने वाली ट्रेनों में समायोजित किया



गया। आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था हेतु GSRTC की बसों को स्टैंडबाय पर रखा गया, हालांकि अंततः उनकी आवश्यकता नहीं पड़ी। वाणिज्य विभाग द्वारा यात्रियों को राहत प्रदान करने के लिए 700 से अधिक रिफ्रिजरेट पैकेट, मुरमुरा एवं बिस्कुट वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त 4 विशेष कार्टर (UTS, PRS, TDR सहायता एवं सहयोग डेस्क) खोले गए तथा 14 से अधिक वाणिज्यिक कर्मचारियों को सुचारु संचालन एवं यात्री सहायता के लिए तैनात किया गया। सभी यात्रियों की शिकायतों एवं सहायता संबंधी आवश्यकताओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया गया।

इसी प्रकार भरूच रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया गया। लगभग 250 यात्रियों को ट्रेन संख्या 19012 से ट्रेन संख्या 22195 में स्थानांतरित कर उनकी यात्रा सुगम बनाई गई। रिफंड चाहने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कार्टटर खोले गए तथा स्थानीय स्वयंसेवी

संस्थाओं (NGOs) के सहयोग से प्रभावित यात्रियों को हल्के जलपान एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई। यात्रियों को गुजराती, हिंदी एवं अंग्रेजी में नियमित घोषणाओं के माध्यम से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु विशेष सहायता व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रभावित यात्रियों को समय पर सहायता मिली, सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हुई तथा रिफंड एवं अन्य सेवाओं का त्वरित निस्तारण किया जा सका। पूरे अभियान के दौरान मंडल के रेल कर्मचारियों ने समर्पण, अनुशासन एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यात्रियों की हरसंभव सहायता की।

वडोदरा मंडल यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं विश्वस्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध यात्रियों को ट्रेन संख्या 19012 से ट्रेन संख्या 22195 में स्थानांतरित कर उनकी यात्रा सुगम बनाई गई। रिफंड चाहने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कार्टटर खोले गए तथा स्थानीय स्वयंसेवी

अहमदाबाद मंडल के कटोसण रोड–रणुज रेलखंड पर 09 से 11 जुलाई के बीच सीआरएस द्वारा संरक्षा निरीक्षण,यात्री रेल सेवाओं के शुभारंभ की दिशा में अहम कदम

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा रेल अवसंरचना के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जा रही है। अहमदाबाद मंडल के कटोसण रोड–रणुज (63 किलोमीटर) रेलखंड का रेल संरक्षा आयुक्त (Commission of Railway Safety) द्वारा 09 से 11 जुलाई, 2026 तक संरक्षा निरीक्षण किया जा रहा है। यह निरीक्षण इस रेलखंड पर यात्री रेल सेवाओं के शुभारंभ की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है।

निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 09 एवं 10 जुलाई, 2026 को मोटर ट्रॉली द्वारा रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया जाएगा, जबकि 11 जुलाई, 2026 को इस रेलखंड पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इंजन स्पीड ट्रायल किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान रेलखंड पर उच्च गति से ट्रेन का संचालन किया जाएगा।

निरीक्षण टीम में रेल संरक्षा आयुक्त (पश्चिम सर्कल) श्री ई. श्रीनिवास, मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) श्री प्रदीप गुप्ता, डायरेक्टर गुजरात रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (G-RIDE) श्री राक कुमार, जनरल मैनेजर (सिविल) G-RIDE श्री शिवेन्द्र कुमार, मुख्य ट्रैक इंजीनियर, मुख्य परिचालन प्रबंधक (जी) तथा निर्माण एवं ओपन लाइन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा इस परिवर्तित ब्रॉडगेज रेलखंड को यात्री यातायात के



लिए स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व ट्रैक की गुणवत्ता, सिमनलिंग व्यवस्था, पुलों, ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) प्रणाली, इंटरलॉकिंग, ट्रैक फिटिंग, बैलास्ट, OHE की ऊँचाई सहित सभी संरक्षा मानकों का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही रेलखंड पर अधिकतम सुरक्षित गति का भी परीक्षण किया जाएगा।

मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने बताया कि वर्तमान में इस रेलखंड पर केवल मालगाड़ियों का

संचालन किया जा रहा है। सीआरएस निरीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद इस मार्ग पर यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे क्षेत्र के यात्रियों को तेज, सुरक्षित एवं सुविधाजनक रेल यात्रा उपलब्ध होगी तथा उत्तरी गुजरात के ग्रामीण एवं दूरी भाग्य क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस रेलखंड के अंतर्गत बेचराजी, खांभेल एवं चाणसमा जैसे

महत्वपूर्ण स्टेशन आते हैं, जो महेशणा एवं पाटण जिलों के प्रमुख केंद्र हैं। यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ होने से स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों, नौकरपेशा लोगों तथा व्यापारियों को बेहतर एवं किफायती आवागमन सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही, देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रसिद्ध बेचराजी मंदिर में दर्शन एवं मेले में भाग लेने आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका विशेष लाभ मिलेगा।

यह परियोजना क्षेत्र की कृषि, लघु उद्योग एवं व्यापारिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेगी। किसानों को अपने कृषि उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। साथ ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

यह उपलब्धि भारतीय रेलवे की आधुनिक, सुरक्षित एवं यात्री-केंद्रित कार्यप्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी तथा समग्र आर्थिक विकास को नई दिशा प्रदान करेगी।

आम जनता से विशेष अपील

संरक्षा की दृष्टि से आम नागरिकों से अनुरोध है कि 09 से 11 जुलाई, 2026 इससे क्षेत्र के यात्रियों को तेज, सुरक्षित एवं सुविधाजनक रेल यात्रा उपलब्ध होगी तथा उत्तरी गुजरात के ग्रामीण एवं दूरी भाग्य क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस रेलखंड के अंतर्गत बेचराजी, खांभेल एवं चाणसमा जैसे



है, इसलिए हमने संबंधित अधिकारियों और रेल मंत्री से संपर्क किया। हमने गुजरात के रेलवे नेटवर्क और मारुति के नेटवर्क को एक साथ जोड़ने के लिए कई विभागों के साथ मिलकर प्रयास किए हैं। आज हमारे लिए एक शुभ दिन है क्योंकि इसका निरीक्षण किया जा रहा है। इस निरीक्षण के पूरा होने के बाद, बेचराजी से लेकर चाणसमा और रणुज तक रेलवे की सभी जांच पूरी हो जाएगी और यदि कोई कमी रह जाती है, तो उसे दूर करने के आदेश दिए जाएंगे ताकि काम पूरा किया जा सके।”

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने बताया कि इस रेलखंड पर लंबे समय से स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों द्वारा यात्री रेल सेवा प्रारंभ करने की मांग की

जा रही थी। किसी भी नए रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू करने से पूर्व रेलवे संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति अनिवार्य होती है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत पश्चिम रेलवे के रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा इस रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 63 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड में प्राथमिक रूप से बेचराजी तक का निरीक्षण सम्पन्न हुआ है। दूसरे दिन बेचराजी से चाणसमा तथा तीसरे दिन चाणसमा से रणुज तक निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण पूर्ण होने के उपरांत रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा आवश्यक सुधार एवं कमीयों के संबंध में सुझाव दिए जाएंगे। सभी आवश्यक कार्य पूर्ण होने तथा संरक्षा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस रेलखंड पर यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। रेलवे का प्रयास है कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र ही इस रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का संचालन प्रारंभ किया जाए। इस रेलखंड के शुरू होने से महेशणा एवं पाटण जिलों के प्रमुख केंद्र जैसे बेचराजी, खांभेल एवं चाणसमा आसपास में जुड़ेंगे। इससे स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों, नौकरपेशा लोगों और व्यापारियों को किफायती आवागमन सुविधा मिलेगी। साथ ही, विश्व प्रसिद्ध बेचराजी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम होगी।

इस परियोजना क्षेत्र की कृषि, लघु उद्योगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी।

वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस : भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में गुजरात का योगदान 17.82%, स्थापित क्षमता 50.386 गीगावाट तक पहुंची

►रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में गुजरात देश का अग्रणी राज्य, कुल स्थापित क्षमता में 15,850.56 मेगावाट पवन ऊर्जा और 32,302.7 मेगावाट सौर ऊर्जा शामिल ►रूफटॉप सोलर में भी राज्य का दबदबा, 13.45 लाख से अधिक इंस्टॉलेशन के जरिए 7408.10 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है ►स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में गुजरात देश में अक्वल, जबकि स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में दूसरे नंबर पर ►राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास से अनुमानित 2.37 लाख प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार का सृजन

गांधीनगर : हर साल 10 जुलाई को ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस ‘डे’ यानी ‘वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस’ मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके स्वच्छ एवं टिकाऊ ऊर्जा पर आधारित भविष्य का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने का लक्ष्य निश्धारित किया है। इतना ही नहीं, परंपरागत ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक तक देश की 50 फीसदी बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हासिल करने का संकल्प भी किया है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात पवन, सौर और रूफटॉप सोलर ऊर्जा क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 50.386 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सर्वाधिक 17.82 फीसदी के योगदान को दिखाती है। गुजरात कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता (15,850.56 मेगावाट) के मामले में भी देश में पहले स्थान पर है। इसके अलावा, राज्य स्थापित सौर



ऊर्जा क्षमता (32,302.7 मेगावाट) में दूसरे स्थान पर है। वहीं, 13.45 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन एवं 7408.10 मेगावाट क्षमता के साथ रूफटॉप सोलर क्षेत्र में भी देश में पहले नंबर पर है।

गुजरात 32,302.7 मेगावाट क्षमता के साथ सौर ऊर्जा क्षेत्र में बना अग्रणी राज्य

गुजरात सौर ऊर्जा क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। मई 2026 तक राज्य की कुल स्थापित सौर ऊर्जा

क्षमता 32,302.7 मेगावाट तक पहुंच गई है। इसमें 23,259.27 मेगावाट ग्राउंड-माउंटेड प्रोजेक्ट्स, 7408.10 मेगावाट रूफटॉप सोलर, 1434.66 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स तथा 200.48 मेगावाट ऑफ-ग्रिड सिस्टम्स (पीएम-कुसुम योजना सहित) शामिल हैं।

राज्य के प्रमुख सोलर पार्कों में चारणाका (749 मेगावाट), राधानेसड़ा (700 मेगावाट) और धोलेरा (300 मेगावाट) शामिल हैं। उधर, कच्छ का

खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क 37.35 गीगावाट की नियोजित क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, जहां मई 2026 तक 15.54 गीगावाट क्षमता हासिल कर ली गई है। उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार ने वर्ष 2016 से आवासीय रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने वाली विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। पीएम सूर्य घर योजना शुरू होने के बाद भी इन प्रयासों को जारी रखा गया है। नतीजतन, राज्य में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में 13 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर लगाए जा चुके हैं, और देश के कुल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में गुजरात का योगदान 21 फीसदी से अधिक रहा है। कृषि क्षेत्र में भी पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट-बी के अंतर्गत मई 2026 तक 22,792 स्वतंत्र ऑफ-ग्रिड सोलर वाटर पंप स्थापित किए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 162.62 मेगावाट है।

गुजरात 15,850.56 मेगावाट क्षमता के साथ पवन ऊर्जा में नंबर वन

देश की पहली विंड पावर पॉलिसी घोषित करने वाला गुजरात पवन ऊर्जा क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है। मई 2026 तक राज्य की स्थापित पवन

ऊर्जा क्षमता 15,850.56 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें कच्छ का योगदान सर्वाधिक 8191.42 मेगावाट है। इसके अलावा, जामनगर (1986.15 मेगावाट), देवभूमि द्वारका (1343.24 मेगावाट), अमरेली (992.90 मेगावाट), राजकोट (869.60 मेगावाट), भावनगर (626.20 मेगावाट), मोरबी (612.10 मेगावाट), सुरेन्द्रनगर (500.60 मेगावाट) और पाटण (208.20 मेगावाट) जिलों का भी उल्लेखनीय योगदान है। राज्य ने 2018 की हाइब्रिड पॉलिसी और गुजरात आरई पॉलिसी 2023 के तहत 2838.07 मेगावाट के विंड-सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं। पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए 80 फीसदी से अधिक टर्बाइन सरकार की ओर से आवंटित भूमि पर स्थापित किए गए हैं। गुजरात सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल ‘अक्षय ऊर्जा सेतु’ के माध्यम से ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए एक पारदर्शी और आसान व्यवस्था बनाई है, जिसके कारण प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को गति मिली है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास से राज्य में अनुमानित 2.37 लाख प्रत्यक्ष और परोक्ष नौकरियों का सृजन हुआ है।

सुदृढ़ नीतियों से गुजरात में

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को मिली गति

गुजरात आज नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बन गया है, जिसमें राज्य सरकार की सुदृढ़ नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 1993 में देश की पहली विंड पावर पॉलिसी घोषित करने के बाद गुजरात ने सौर ऊर्जा नीति (2009, 2015 और 2021), वेस्ट-टू-एनर्जी और स्मॉल हाइडल नीति (2016) तथा विंड-सोलर हाइब्रिड पॉलिसी (2018) सहित अनेक महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं। वर्ष 2022 की संशोधित वेस्ट-टू-एनर्जी नीति और 24 दिसंबर, 2025 से 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहने वाली गुजरात इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2025 के जरिए सौर, पवन, हाइब्रिड, विकेद्रीकृत प्रोजेक्ट्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के लिए एकीकृत नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2023 की नीति के जरिए क्षमता की सीमा को हटाकर सभी प्रकार की परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। इसके अलावा, 2025 की नीति में विकेद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स

को गति देने, ग्रिड कनेक्टिविटी को आसान बनाने, पुराने पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स की रीपाव्रिंग, बैटरी स्टोरेज के एकीकरण, निजी क्षेत्र की भागीदारी, नवीकरणीय ऊर्जा के कुल उत्पादन और रिसाइक्लिंग, ग्रुप और वर्चुअल नेट मीटिंग, कृषि और रूफटॉप सोलर सहित ग्रीन जॉब्स और कौशल विकास को बढ़ावा दिया गया है।

नवीकरणीय ऊर्जा के भविष्य की ओर गुजरात के बढ़ते कदम

गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगातार नए मील के पथर स्थापित कर रहा है। राज्य में मई 2026 तक कुल 1531 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं पर काम चल रहा है। जिनमें 1320 सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स (3.377 गीगावाट), 115 पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स (3.913 गीगावाट) और 96 हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स (4.869 गीगावाट) शामिल हैं। गांधीनगर में आयोजित आरई-इन्वेस्ट 2024 के दौरान गुजरात ने वर्ष 2030 तक 105 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निश्धारित किया है, जो भारत के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य में लगभग 20 फीसदी का योगदान देगा।

गुजरात में किसानों का डेटा रहेगा 100 प्रतिशत सुरक्षित कृषि विभाग ने किया ‘विभागीय डेटा समिति’ का गठन

►केंद्र सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट तथा गुजरात स्टेट डेटा गवर्नंस फ्रेमवर्क के अंतर्गत डीडीसी का गठन ►किसानों की गोपनीय जानकारी रहेगी सुरक्षित, बिचौलियों और धोखाधड़ी पर लगेगा नियंत्रण ►लाभार्थी किसानों तक राज्य सरकार की सहायता अधिक तेजी से पहुंचेगी

गांधीनगर : डिजिटल इंडिया के संकल्प को गति देते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कृषि, किसान कल्याण तथा सहकारिता विभाग ने किसानों की जानकारी की सुरक्षा के लिए ‘विभागीय डेटा समिति’ (डीडीसी) का गठन किया है। केंद्र सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीटी एक्ट) की भावना के अनुसार राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों का व्यक्तिगत, वित्तीय तथा कृषि संबंधी डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे, उसका उपयोग नियमों के अनुसार तथा किसानों की सहमति से ही किया जाए। विभागीय

डेटा समिति कृषि विभाग तथा उससे जुड़े बोर्ड-निगमों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के डेटा का वैज्ञानिक, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करेगी।

सिान हित को प्राथमिकता

डिजिटल युग में किसानों का डेटा भूमि और फसल जितना ही महत्वपूर्ण है। यदि डेटा का वैज्ञानिक, सुरक्षित और पारदर्शी वह सुरक्षित रहेगा, तो योजनाओं का लाभ भी सही व्यक्ति तक पहुंचेगा तथा धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।

उच्च स्तरीय समिति निगरानी रखेगी

इस समिति का नेतृत्व कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अथवा सचिव करेंगे। समिति में विभागीय डेटा अधिकारी, सदस्य सचिव, मुख्य सूचना

सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), उप निदेशक (आईटी), आईसीटी अधिकारी, विधिक अधिकारी, आईटी विशेषज्ञ तथा विभाग के सभी बोर्ड-निगमों, विश्वविद्यालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों को शामिल किया गया है।

डेटा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाएगा

कृषि विभाग के सभी डेटा सेट का ओपन, शेयरेबल, प्रतिबोधित, संवेदनशील तथा नेगेटिव लिस्ट; इन पांच श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाएगा। इससे मौसम, कृषि तकनीक, बाजार भाव जैसी सार्वजनिक उपयोग की जानकारी किसानों तक आसानी से पहुंचाई जा सकेगी, जबकि किसानों की व्यक्तिगत, बैंकिंग तथा अन्य निजी जानकारी को संवेदनशील श्रेणी में रखकर पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा।

केंद्र सरकार के डीपीडीपी कानून का सख्त पालन किया जाएगा

समिति सुनिश्चित करेगी कि किसानों के डेटा का संग्रह, उपयोग तथा प्रसंस्करण मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अथवा सचिव करेंगे। समिति में विस्तृत जानकारी सरकारी नियमों के अनुसार किया जाए। इस व्यवस्था द्वारा किसानों की व्यक्तिगत

जानकारी के अनधिकृत उपयोग को रोक जा सकेगा तथा डेटा सुरक्षा को कानूनी संरक्षण मिलेगा।

किसानों की सहमति के बिना डेटा का उपयोग नहीं होगा

इस व्यवस्था में नागरिक सहमति (कंसेंट मैनेजमेंट) को विशेष महत्व दिया गया है। किसानों के डेटा के उपयोग के लिए उनकी सहमति का संपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित, ऑडिटेबल तथा ट्रैकेबल रहेगा।

यदि किसी भी स्तर पर सहमति संबंधी नियमों का उल्लंघन होता है, तो उसकी तत्काल सूचना राज्य डेटा प्राधिकरण (स्टेट डेटा अथॉरिटी-एसडीए) को दी जाएगी।

डेटा ब्रीच पर तत्काल कार्यवाही समिति किसानों के डेटा से संबंधित किसी भी सुरक्षा घटना अथवा डेटा ब्रीच पर तत्त निगरानी रखी जाएगी। यदि किसी भी प्रकार का डेटा उल्लंघन होगा, तो उसकी तत्काल सूचना राज्य के मुख्य डेटा अधिकारी तथा अन्य सक्षम अधिकारियों को दी जाएगी, ताकि शीघ्र कार्रवाई की जा सके। यह व्यवस्था किसानों की डिजिटल सुरक्षा को चौबीसों घंटे मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करेगी।

किसानों के लिए अधिक प्रभावी योजनाएं बनेंगी

सुरक्षित एवं प्राणित डेटा उपलब्ध होने से कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, इनोवेशन तथा साक्ष्य-आधारित निर्णय प्रक्रिया को गति मिलेगी। परिणामस्वरूप किसान कल्याण योजनाएं अधिक प्रभावी, सटीक तथा वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप बनेंगी।

नई व्यवस्था से किसानों को क्या लाभ होगा ?

►किसानों की व्यक्तिगत,बैंकिंग तथा अन्य संवेदनशील जानकारी संपूर्णरूप से सुरक्षित रहेगी

►डेटा के दुरुपयोग, अनधिकृत प्रवेश तथा साइबर जोखिमों पर प्रभावी निगरानी रखी जाएगी

►भविष्य की कृषि नीतियां एवं योजनाएं वास्तविक आंकड़ों तथा वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाएंगी

►कृषि सब्सिडी, फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा राहत तथा अन्य सरकारी सहायता का वितरण अधिक तेज, पारदर्शी और सटीक होगा

►पात्र किसानों तक सीधे लाभ पहुंचेगा

वन विभाग की नर्सरियों से पौधे चाहिए ? सिर्फ एक कॉल करें और लिंक मिलते ही सभी नर्सरियों की जानकारीयाँ मिल जाएंगी

►आप पौधे लगाना चाहते हैं, लेकिन गुजरात वन विभाग की निकटस्थ नर्सरी खोजने में कठिनाई हो रही है ? तो अब इसका एक आसान उपाय है। बस, 8320002000 मोबाइल नंबर पर डायल करें। यह कॉल अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन पर एक लिंक के साथ एसएमएस आएगा। यह लिंक खोलने पर वन विभाग की सभी नर्सरियों की जानकारी मिल जाएगी

►“मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में समग्र गुजरात में लोग पेड़-पौधे लगाकर राज्य को हरित बनाएँ; इसके लिए वन विभाग प्रतिबद्ध है। नागरिकों को उनके आसपास स्थित वन विभाग की नर्सरियों से आसानी से पौधे मिल सकें; इसके लिए सरल व्यवस्था की गई है। वन विभाग के सामाजिक वनीकरण विंग द्वारा 11.80 करोड़ पौधे नागरिकों को देने के लिए तैयार किए गए हैं” : वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोदवाडिया

गांधीनगर : आप पौधे लगाना चाहते हैं, लेकिन गुजरात वन विभाग की निकटस्थ नर्सरी खोजने में कठिनाई हो रही है ? तो अब इसका एक आसान उपाय है। बस, 8320002000 मोबाइल नंबर पर डायल करें। यह कॉल अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन पर एक लिंक के साथ एसएमएस आएगा। इस लिंक को खोलने पर आपके क्षेत्र के वन विभाग के सामाजिक वनीकरण विभाग की नर्सरी की संपर्क जानकारी, गूगल मैप पर उसका स्थान तथा संबंधित वन अधिकारियों के मोबाइल नंबर सहित सारी जानकारी मिल जाएगी। इस व्यवस्था के कारण लोगों को वन विभाग की नर्सरियों से पौधे प्राप्त करने में सरलता रहेगी। इसके अलावा; यदि आप 8320002000 पर ‘Hi’ लिखकर एसएमएस या व्हाट्सएप संदेश भेजेंगे, तो भी आपको एक वेब लिंक वाला एसएमएस मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करने से एक मेन्यू खुलेगा, जिसमें गुजरात वन विभाग की सभी नर्सरियों, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स (आरएफओ), इको-टूरिज्म साइट्स तथा वन से संबंधित अन्य सेवाओं की संपर्क जानकारी सहित अनेक विकल्प मिलेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जन भागीदारी द्वारा देश के ग्रीन कवर का विस्तार बढ़ाने के लिए ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान शुरू किया है और गुजरात ने उनके इस आह्वान को स्वीकार कर लिया है। गुजरात वन विभाग की नर्सरी खोजने में कठिनाई हो रही है ? तो अब इसका एक आसान उपाय है। बस, 8320002000 मोबाइल नंबर पर डायल करें। यह कॉल अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन पर एक लिंक के साथ एसएमएस आएगा। इस लिंक को खोलने पर आपके क्षेत्र के वन विभाग के सामाजिक वनीकरण विभाग की नर्सरी की संपर्क जानकारी, गूगल मैप पर उसका स्थान तथा संबंधित वन अधिकारियों के मोबाइल नंबर सहित सारी जानकारी मिल जाएगी। इस व्यवस्था के कारण लोगों को वन विभाग की नर्सरियों से पौधे प्राप्त करने में सरलता रहेगी। इसके अलावा; यदि आप 8320002000 पर ‘Hi’ लिखकर एसएमएस या व्हाट्सएप संदेश भेजेंगे, तो भी आपको एक वेब लिंक वाला एसएमएस मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करने से एक मेन्यू खुलेगा, जिसमें गुजरात वन विभाग की सभी नर्सरियों, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स (आरएफओ), इको-टूरिज्म साइट्स तथा वन से संबंधित अन्य सेवाओं की संपर्क जानकारी सहित अनेक विकल्प मिलेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जन भागीदारी द्वारा देश के ग्रीन कवर का विस्तार बढ़ाने के लिए ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान शुरू किया है और गुजरात ने उनके इस आह्वान को स्वीकार कर लिया है।



वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोदवाडिया ने कहा, “मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में समग्र गुजरात को अधिक हरित बनाने के अभियान में हजारों लोग जुड़े और वृक्षारोपण के लिए नागरिकों को उनके आसपास की वन विभाग की नर्सरियों से पौधे आसानी से मिल सकें; इसके लिए सुंदर व्यवस्था की गई है। इस वर्ष वन विभाग की सामाजिक वनीकरण विंग द्वारा 11.80 करोड़ पौधे नागरिकों की वितरण के लिए तैयार किए गए हैं।” वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री प्रवीण माळी ने कहा, “वन विभाग की इस नागरिक-केन्द्रित पहल अंतर्गत गुजरात वन विभाग ने एक इन-हाउस डिजिटल हेल्पलाइन सिस्टम शुरू किया है, जो राज्यभर के लोगों को सहायता तथा शिकायतों के निवारण

विभाग की किसी भी नर्सरी से पौधों के आकार के आधार पर 5 से 15 रुपए तक की मामूली कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले पौधे खरीद सकते हैं। समग्र राज्य में वन विभाग की कुल 453 नर्सरियां स्थित हैं। 15 × 25 सेंटीमीटर या 10 × 20 सेंटीमीटर आकार की पॉलीबैग में लगाए गए पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। जो नागरिक निःशुल्क या रियायती दर पर पौधे प्राप्त करना चाहते हैं, वे अवरोधों का पता लगा सकते हैं तथा विद्युतीकृत क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश या मानव गतिविधियों की तुरंत सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुँचा सकते हैं।”

वन्यजीवों के रेस्क्यू के अनुरोध के लिए 1926 हेल्पलाइन डायल करें

वन विभाग से संबंधित कोई शिकायत हो या अधिक सहायता की आवश्यकता हो; ऐसे मामलों में नागरिक वन विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1926 पर संपर्क कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन पर भी प्रतिदिन लगभग 30 से 40 कॉल प्राप्त होते हैं। यह संपूर्ण सिस्टम वन विभाग द्वारा इन-हाउस (स्वयं के तरीके से) विकसित किया गया है और इसका संचालन भी वही कर रहा है, यह बिना किसी अतिरिक्त खर्च के सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग पर विभाग के जोर को दर्शाता है। यह पहल वन विभाग से सहायता मांगने वाले नागरिकों के लिए आशीर्वाद समान है।